भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3877

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी अध्ययन

3877. श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से किसानों के उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण का विशेषतः मूल्यांकन करते हुए कोई व्यापक प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो ऐसा आकलन कब तक किए जाने की योजना है;

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश में किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुँचने के लिए लक्षित योजनाओं और नीतियों के संदर्भ में अपनाई जा रही विशिष्ट कार्यनीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत डिजिटल अंतर को पाटने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाओं में समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता गाथा का संकलन जारी किया है, जिन्होंने डीएएंडएफडब्ल्यू और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के समामेलन से अपनी आय में दो गुना से अधिक वृद्धि की है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वें दौर) में ₹6,426 से बढ़कर 2018-19 (एनएसएस 77वें दौर) में ₹10,218 हो गई है।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-2024
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996
ग्रामीण एमपीसीई के % के रूप में अंतर	83.9	69.7

(ग) एवं (घ): भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए निम्नलिखित एकीकृत कार्यनीति की पहचान की है:

(i) फसल उत्पादन/ उत्पादकता में वृद्धि
(ii) उत्पादन लागत कम करना
(iii) किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी उपज का लाभकारी मूल्य:
(iv) कृषि विविधीकरण
(v) फसलोपरांत मूल्य संवर्धन का विकास करना
(vi) सतत कृषि और फसल हानि को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सभी योजनाएँ/कार्यक्रम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सहित भारत में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के संबंध कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
8. नमो ड्रोन दीदी

9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एस.एच. एंड एफ.)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आई.एस.ए.एम.)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के अतंर्गत देश में कृषि के लिए एक सुदृढ़ डिजिटल एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और एक व्यापक सॉइल उर्वरता और प्रोफ़ाइल मैप जैसे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण की परिकल्पना की गई है। फलस्वरूप यह, नवाचार किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देगा और सभी किसानों को समय पर फसल संबंधी विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगा। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात, जियोरेफरेंस्ड विलेज मैप्स, क्रॉप सोवन रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, इन सभी को राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाया और रख-रखाव किया जाता है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य सहित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

*****